मूल्य 1 रु.
वर्ष: 15 - अंक : 73, मुंबई, शनिवार, 5 जुलाई, 2025 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादक: दिलशाद एस. खान

दैनिक
मुंबई हलचल
भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®
अब हर सच होगा उजागर

DESI™ VILLAGE
RESTAURANT & CAFE
DUBAI

फडणवीस समेत 5 विधायकों को
राहत
हाई कोर्ट का प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों को झटका

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। राज्य में विधानसभा के लिए गत वर्ष आम चुनाव कराए गए। नियमों के अनुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होने तथा प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियां होने का हवाला देते हुए दक्षिण-पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रफुल्ल गुड्धे पाटिल ने हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर की। इसी तरह से से राजुरा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुभाष धोटे ने विधायक देवराव भोंगाडे, दक्षिण नागपुर में गिरीश पांडव ने विधायक मोहन मते, बल्लारपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे संतोष सिंह रावत ने विधायक सुधीर मुनगंटीवार और चिमूर क्षेत्र में सतीश वारजुरकर ने विधायक कीर्तिकुमार भांगडिया और के खिलाफ याचिका दायर की थी।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

परिवहन मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन

मुंबई में ओला, उबर की बाइक-टैक्सी सेवा बंद

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। मुंबईकरों के लिए सुविधाजनक लगने वाली लेकिन अवैध रूप से चल रही ओला और उबर की बाइक टैक्सी सेवाओं को आखिरकार बंद कर दिया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा खुद किए गए स्टिंग ऑपरेशन में इस घटना का खुलासा होने के बाद परिवहन विभाग ने यह कठोर कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को खुद एक सामान्य यात्री की तरह ऐप पर बाइक बुक की।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

'रैपिडो' अभी भी शुरू

ओला और उबर के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब प्रशासन को रैपिडो से चुनौती मिल रही है। इसलिए मुंबईकरों का ध्यान इस बात पर है कि रैपिडो की अवैध सेवा कब बंद होगी और सभी ऐप के लिए एक जैसे नियम कब लागू किए जाएंगे।

पुणे दुष्कर्म मामले में चौकाने वाले खुलासा

डिलीवरी ब्वॉय नही पीड़िता का दोस्त..

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। पुणे पूरे शहर में हलचल मचा देने वाले कोंढवा रेप केस ने चौंकाने वाला और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि जिस महिला ने शिकायत की थी कि एक अज्ञात डिलीवरी बॉय ने उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया और जिस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वे दोनों पिछले एक साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा शुरूआती अनुमान कि दोनों के बीच सहमति से संबंध थे, ने मामले को पूरी तरह बदल दिया है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी। उनके मुताबिक, युवक को हिरासत में लिया गया है और 500 सीसीटीवी खंगाले गए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

'शायरी नहीं शाह के लिए मुजरा भी करेंगे शिंदे'
संजय राउत का 'जय गुजरात' पर तंज

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र में आज दशकों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर साथ दिखेंगे। दोनों ठाकरे बंधु हिंदी भाषा पर अपनी जीत का जश्न मनाने वर्ली में विशाल मोर्चा निकाल रहे है। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों भाइयों के साथ आने से महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ रही है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, यह हमारे लिए उत्सव जैसा है कि शीर्ष नेता (शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे) सालों बाद, जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे। अब वे एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

राउत ने साधा निशाना

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में जय गुजरात का नारा लगाया। जिसके बाद राज्य में सियासी बवाल मच गया। विपक्षी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने डिप्टी सीएम पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करते हुए कहा, एकनाथ शिंदे अमित शाह के लिए मुजरा और मुशायरा भी कर सकते है। उनका मुजरा तो चल ही रहा है। मैं उनको पहचानता हूं, वो एक मराठी कविता भी नहीं पढ़ सकते। अगर उन्हें अमित शाह के आशीर्वाद से सत्ता में रहना है तो ये मुजरा उन्हें करना पड़ेगा, इसलिए किया है और करने दो।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

ऋण का बोझ घटा?

असल कहानी मीडिया हेडलाइन्स के नीचे कहीं छिपी होती है। ताजा रिपोर्ट को ही लें, तो उससे यह कहानी भी उभरती है कि फौरी उपभोग के मकसद से लिए गए ऋण की मात्रा असल में बढ़ी है।

मीडिया के एक हिस्से ने इसी रिपोर्ट से हेडलाइन निकाली है कि भारत में घरेलू कर्ज की मात्रा जून 2024 की तुलना में पिछले दिसंबर तक आकर एक प्रतिशत प्रतिशत घट गई। जून 2024 में घरेलू ऋण जीडीपी की तुलना में 42.9 प्रतिशत था। दिसंबर 2024 में 41.9 फीसदी रहा। हालांकि दिसंबर 2023 (40 प्रतिशत) और जून 2021 (36.6 प्रतिशत) की तुलना में यह फिर भी ज्यादा था, परंतु पिछले साल की दूसरी छमाही में स्थिति सुधरी। मगर ये हेडलाइन्स की बात है। असल कहानी कहीं इनके नीचे छिपी होती है। ताजा रिपोर्ट को ही लें, तो उससे यह कहानी भी उभरती है कि असल में फौरी उपभोग के मकसद से लिए गए ऋण की मात्रा बढ़ी है। मार्च 2025 में कुल घरेलू कर्ज के बीच इस ऋण का हिस्सा 54.9 फीसदी था। यानी जहां ऋण की मात्रा घटी, वो हाउजिंग लोन या कारोबार के मकसद से लिए गए कर्ज हैं। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। असल में ये सभी बाजार के सिकुड़ने और आम जन के स्तर पर आमदनी घटने/ गतिरुद्ध होने के आम ट्रेंड की ही पुष्टि हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में बिक्री से लेकर रोजाना कैलोरी उपभोग तक से संबंधित सामने आए ताजा आंकड़े कुल मिलाकर एक ही तरफ इशारा करते हैं। यह है समाज में विषमता का लगातार विकराल रूप लेना। इसके बीच बेहतरी कुछ तबकों तक सीमित है, मगर कुल आंकड़ों में इससे सुधार जाहिर हो जाता है। वैसे भी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े सिर्फ बैंकों या संगठित वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण से संबंधित हैं। आम जन के स्तर पर तो आज महाजनी प्रथा के लौटने के संकेत देश के कई हिस्सों से मिले हैं। वहां लिए गए कर्ज और उस पर चुकाए जाने वाले असमान्य ब्याज दर का शायद ही कोई रिकॉर्ड किसी सरकारी संस्था के पास होता है। इसलिए मीडिया हेडलाइन्स जो कहानी बताते हैं, सामाजिक-आर्थिक मामलों में हकीकत उससे दूर बनी रहती है।

नर्सिंग न केवल पेशा, बल्कि सेवा, समर्पण व करुणा का प्रतीक है : एएसपी करियारे

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विश्वास सोशल वैलफेयर सोसायटी (उपासना एजुकेशन ट्रस्ट) में नर्सिंग के बच्चों का प्रमाण पत्र वितरण समारोह स्थानीय जेपी वर्मा कॉलेज के सभागार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी ट्रेफिक रामगोपाल करियारे थे। अध्यक्षता जेपी वर्मा कॉलेज के प्रिंसिपल एसएल निराला ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। एएसपी करियारे ने कहा, नर्सिंग न केवल एक पेशा है, बल्कि यह सेवा, समर्पण और करुणा का प्रतीक है। हर आपातकाल परिस्थितियों में वो घर परिवार भूलकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास करती हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। करियारे ने नर्सिंग छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा, आप सभी ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। अब आप समाज की सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज के प्रिंसिपल एसएल निराला ने भी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 3 बैच के बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम सियान चेतना अभियान पर आधारित था। संस्था की छात्राओं के द्वारा एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। जो लोगों के द्वारा अपने घर के वृद्धजन को वृद्धाश्रम में रखने या घर से बाहर निकाल देने के विषय में था। एक छत्तीसगढ़ी नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में ट्रेफिक मास्टर ट्रेनर एसआई उमाशंकर पांडे, सिम्स की रिटायर्ड स्टाफ नर्स अंजली हक भी शामिल थी। सभी ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया तथा उनके उज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष मिंटू अरोरा, उपाध्यक्ष मानस्यु अरोरा, सचिव संध्या चंद्रसेन, मनीषा सैमुएल, मानसी सिंग, ओमकार बघेल, प्रकाश सोनछत्र, अभिषेक जोशी, दीप जोशी एवं संस्था के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। छात्रों के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण था। कुछ छात्रों की आँखों में खुशी के आँसू भी देखे गए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गईं, जिससे वातावरण उत्साहपूर्ण हो गया।

गोदरेज कैपिटल के लेंडिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्सफोर्स एआई-आधारित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा

मुंबई। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा गोदरेज कैपिटल और दुनिया नंबर 1 एआई-सीआरएम कंपनी सेल्सफोर्स ने आज एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य गोदरेज कैपिटल की सहायक कंपनियों को डिजिटल लोन प्रणाली को और बेहतर बनाना और पूरे भारत में बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करना है। इस पहल के लिए डेलॉइट इंडिया को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है, जो सेल्सफोर्स के उन्नत प्लेटफॉर्म्स को गोदरेज कैपिटल की लोन व्यवस्था में तेजी से और आसानी से जोड़ने में मदद करेगा। गोदरेज कैपिटल हमेशा से नए इनोवेशन और जनरेटिव एआई आधारित तकनीकों को अपनाने में आगे रहा है। गोदरेज कैपिटल ने इस साझेदारी के माध्यम से एक भविष्य के लिए तैयार, डिजिटल रूप से मजबूत लोन व्यवस्था बनाने की साझा सोच को साकार किया है। डेलॉइट के पास बड़े पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन देने का अनुभव है, जिससे गोदरेज कैपिटल के सभी उत्पादों में कामकाज की गति, ग्राहक अनुभव और जोखिम समझदारी में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

इस सहयोग के तहत, कंपनी अपने लोन ओरिजिनेशन सिस्टम(एलओएस) को सेल्सफोर्स द्वारा संचालित एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म में एकीकृत कर अपनी लोन प्रक्रिया को और मजबूत बना रहा है। यह पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो में, पहले से मौजूद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआरएम) सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इस नई तकनीकी व्यवस्था से लोन प्रक्रिया पहले से ज्यादा स्मार्ट, आसान और व्यक्तिगत बन जाएगी - आवेदन से लेकर लोन मिलने तक का पूरा सफर तेज और सुगम होगा। इसका उद्देश्य लोन प्रोसेस में लगने वाला समय घटाना, ज्यादा सटीकता लाना और देशभर के लोगों और व्यवसायों को बेहतर तरीके से क्रेडिट (लोन) सुविधा देना है। सेल्सफोर्स की एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कंपनी एक तेज और डेटा-आधारित लोन प्रक्रिया तैयार कर रही है, जिससे स्मार्ट तरीके से अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री (क्रॉस-सेलिंग), जोखिम प्रबंधन में सुधार और बड़े पैमाने पर ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर अनुभव मिल सकेगा। कंपनी को अपने ग्राहकों की पूरी जानकारी एक ही जगह (360-डिग्री व्यू) में मिल रही है – चाहे वे किसी भी प्रोडक्ट, चैनल या संपर्क माध्यम से जुड़े हों। इससे कंपनी को बेहतरीन ग्राहक सेवा देने, तेजी से काम करने और कम मैन्युअल प्रक्रिया में पूरा लोन सिस्टम संभालने में मदद मिल रही है। मनीष शाह, एमडी और सीईओ, गोदरेज कैपिटल ने कहा: गोदरेज कैपिटल में हमारा फोकस टेक्नोलॉजी पर है, और हम लगातार जनरेटिव एआई में निवेश कर रहे हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को बड़े स्तर पर पहुंचा सकें। सेल्सफोर्स जैसी एआई आधारित ग्लोबल कंपनी के साथ हमारा यह सहयोग हमारी प्रयासों को और मजबूत करता है। इससे हम ग्राहकों को और भी स्मार्ट क्रेडिट अनुभव दे सकते हैं, कामकाज को ज्यादा कुशल बना सकते हैं, और तेजी से व्यक्तिगत सेवाएं दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह साझेदारी दिखाती है कि हम दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी का उपयोग वास्तविक वित्तीय समस्याएं हल करने और भारत की आर्थिक तरक्की में योगदान देने के लिए कर रहे हैं, एक ऐसा कर्ज. तंत्र बनाकर जो ज्यादा समावेशी, तेज और लचीला हो। अरुंधती भट्टाचार्य, अध्यक्ष और सीईओ, सेल्सफोर्स - दक्षिण एशिया ने कहा: वित्तीय सेवा क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां टेक्नोलॉजी केवल सिस्टम को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि यह पूरी तरह से यह बदल रही है कि संस्थाएं अपने ग्राहकों से कैसे जुड़ती हैं, निर्णय कैसे लेती हैं और सेवाएं कैसे देती हैं। इस डिजिटल-प्रथम दुनिया में, भविष्य उन्हीं का होगा जो समझदारी, तेजी और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। एआई इस बदलाव का केंद्र है–यह तेजी से निर्णय लेने, ग्राहकों को गहराई से समझने और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत सेवा देने में मदद करता है। गोदरेज कैपिटल इस क्षेत्र में एक साहसी इनोवेटर के रूप में उभर कर सामने आया है, जो ग्राहक को सबसे पहले रखने की सोच को डिजिटल सोच के साथ जोड़ रहा है। वे सिर्फ भारत के एमएसएमई (छोटे और मध्यम उद्योगों) के लिए नहीं, बल्कि हर उधारकर्ता, उद्यमी और परिवार के लिए कर्ज सेवाओं को नए तरीके से तैयार कर रहे हैं, जो देश की प्रगति में योगदान देता है। हमें गर्व है कि हम इस सफर में उनका साथ दे रहे हैं, एक एआई-चालित प्लेटफॉर्म के जरिए जो डेटा, समझ और स्पीड को एक साथ लाकर समावेशी विकास की नई राह खोल रहा है।

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक-दिलशाद एस खान द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व), मुंबई-68 से मुद्रित व मुंबई हलचल, साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी-2-301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर, एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, फोन:9619102478 /9821238815
email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: दिलशाद एस खान, समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

दिवा-मुंबई सीएसएमटी लोकल चलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना

मुंबई हलचल/संवाददाता

ठाणे। मध्य रेल प्रशासन से पूर्व में उपोषण धरना, मोर्चा निकालने व कई बार निवेदन देकर मांग करने के बावजूद दिवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए लोकल सेवा शुरू नहीं हो पाई है। इसके चलते दिवा स्टेशन के रेल यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर लोकल ट्रेन में सफर करना पड़ रहा है। इस मांग को लेकर समाजसेविका अश्विनी अमोल केंद्रे ने दिवा स्टेशन (पूर्व) परिसर में अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इस

आंदोलन को महिलाओं और लोकल यात्रियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। दिवा की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। यहां रहने वाले हजारों लोग रोजाना मुंबई और आसपास के उपनगरों में रोजी-रोटी के लिए लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। सुबह शाम भारी भीड़ के कारण दिवा के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोकल ट्रेनें कल्याण से आती हैं वो पहले ही खचाखच भरी रहती हैं। ऐसे हालत में दिवा के यात्रियों को ट्रेन में चढ़ पाना कठिन हो गया है। काम पर पहुंचने की मजबूरी में लोगों को ट्रेन में लटक कर सफर करना पड़ता है। समाजसेविका अश्विनी अमोल केंद्रे ने कहा कि रेलवे प्रशासन व स्थानीय नेता दिवा के यात्रियों की परेशानी को लेकर गंभीर नहीं है। मराठी मुद्दे को लेकर लड़ने वाले चुप क्यों है। आखिर एक मराठी स्त्री 4 दिन से आंदोलन कर रही है। फिर मराठी मराठी कर लड़ने वाली पार्टियां कहा है।आखिर मराठी महिला के लिए ।मराठी लोगों की जान बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आती।

युवा संस्था द्वारा आयोजित 'बाल मित्र' कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। युवा संस्था द्वारा बाल संरक्षण-बाल मित्र के रूप में हमारा दायित्व विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला में मालवणी, कांदिवली, मानखुर्द और बांद्रा से विशेष रूप से युवा, महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। बाल अधिकार कार्यकर्ता जरीन अंसारी ने बताया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था-समाज के सभी वर्गों को जागरूक करना, बाल संरक्षण के बारे में जागरूक करना और बाल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाना। साथ ही, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बाल संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेना और बाल मित्र के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना था। कार्यशाला में

भाग लेने वाले युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सक्रिय रूप से चर्चा की। महिलाओं ने घर और स्कूल के बाहर बच्चों पर पड़ने वाले दबाव, यौन शोषण की संभावना और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने दैनिक कार्यों में बाल अधिकारों से जुड़ी चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गयाः बाल अधिकार एवं कानून (जैसे जेजे एक्ट, पोस्को) बाल शोषण के प्रकार एवं रोकथाम के उपाय, स्थानीय स्तर पर सखी सावित्री समिति, बाल संरक्षण समिति, पुलिस एवं सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय, बाल संरक्षण कानून एवं स्थानीय व्यवस्था, बाल शोषण के प्राथमिक लक्षण, बच्चों के साथ संवाद एवं विश्वास, बाल मित्र की अवधारणा एवं उसकी जिम्मेदारियाँ कार्यशाला के अंत में सहभागी युवाओं एवं महिलाओं ने शपथ ली कि मैं अपने क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा के लिए सजग रहूँगा। सभी प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्र में सक्रिय बाल मित्र के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया। स्थानीय स्तर पर संरक्षण व्यवस्था, विद्यालयों, अभिभावकों, युवा समूहों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया गया तथा बाल मित्र के रूप में आगामी महीनों में विभिन्न बस्तियों में जागरूकता अभियान, शिविर एवं बाल अधिकार प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँगे। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में आप किस प्रकार योगदान देते हैं, यह आपके क्षेत्र या आपके कौशल के अनुसार महत्वपूर्ण है। युवा संगठन, बाल अधिकार के समन्वयक प्रकाश भावरे ने कहा कि बाल संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

मां काली की प्रतिमा खंडित कर कानपुर में माहौल बिगड़ने की कोशिश, दो गिरफ्तार

मुंबई हलचल/संवाददाता

कानपुर। यहां सांप्रदायिक सद्भाव के दुश्मन अराजक तत्व माहौल बिरने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मां काली की प्रतिमा खंडित करके माहौल बिगड़ने की कोशिश की। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र के भेवली गांव का है। जहां मां काली मंदिर में भोर पहर लगभग चार बजे काली प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों द्वारा दो अधेड़ व्यक्तियों को मंदिर के अंदर से ही पकड़ा गया, जिसमें से एक गैर समुदाय का है। मौके पर पहुंची पुलिस को जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी पारस ने बताया कि मध्य रात्रि दो अधेड़ व्यक्ति मंदिर के पास मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर चले गए और भगवान श्रीराम और अन्य देवी-देवताओं को गालियां देते हुए तोड़फोड़ कर रहे थे। आवाज सुनकर पुजारी ने अपने साथ रह रहे एक बच्चे लवकुश पुत्र रामगोपाल को गांव के अंदर भेजा। इसके बाद शोर मचाकर अन्य लोगों को बुलवाया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तोड़फोड़ कर रहे दोनों अधेड़ व्यक्तियों को मंदिर के अंदर ही बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों शीतलाप्रसाद निषाद (50) पुत्र शत्रुघ्न निवासी 112 श्यामनगर कानपुर और शाहिद (45) निवासी बासमंडी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों ने ऐसा क्यों किया इस बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद निकले नतीजे के आधार पर दोनों को जेल भी भेजा जाएगा।

(पृष्ठ 1 का समाचार)

फडणवीस समेत 5 विधायकों को राहत

शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाएं ठुकरा दीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका में कहा गया कि 1 जनवरी 2025 को निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17-सी भाग-I और भाग-II और बाकी डॉक्यूमेंट्स की आपूर्ति के लिए चुनाव आयोग के पास आवेदन किया गया। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मून ने कहा कि 2 अप्रैल 2025 को फिर से चुनाव आयोग को स्मरण पत्र भेजा गया जिसमें दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए पुनः अनुरोध किया गया किंतु याचिका दायर किए जाने तक किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव-2024 के संचालन से संबंधित सम्पूर्ण वीडियोग्राफी, वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, नियमों में निहित लागू दिशानिर्देशों की हैंडबुक, प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराने का आदेश देने का अनुरोध किया। इसी तरह से फॉर्म 17-सी भाग-I और भाग-II की प्रति उपलब्ध कराने के आदेश भी चुनाव आयोग को देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया। याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मून ने कहा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के संचालन से संबंधित दर्ज पूरी जानकारी को पुस्तिकाओं और नियमों में निहित लागू दिशानिर्देशों और प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित रखने के आदेश दिए जाएं। अंतरिम राहत के रूप में वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिका में दर्ज संबंधित दस्तावेजों की पूरी जानकारी सुरक्षित बनाए रखने का आदेश जिला चुनाव अधिकारी को देने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक यह है कि चुनाव की अधिसूचना से पहले और चुनाव के दिन मतदान के दौरान भी पूरी तरह से कुप्रबंधन था। मशीनों को समय से पहले नहीं बदला गया और फर्जी मतदान सहित अन्य अनियमितताएं पाई गईं और रिपोर्ट की गईं जो बहुत ही संदिग्ध थीं। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव मैनुअल और पुस्तिकाओं में निर्धारित आदेश और प्रक्रिया के विरुद्ध थीं।

परिवहन मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन

इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्होंने इस सेवा की खामियों और अवैध प्रकृति को उजागर किया। कहा जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा न हो और नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए यह कार्रवाई की गई। इस खुलासे के बाद परिवहन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस से संपर्क किया और ओला और उबर दोनों को अपने ऐप से बाइक टैक्सी का विकल्प तुरंत हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद अब यह सेवा बंद कर दी गई है। ओला और उबर के खिलाफ कार्रवाई तो की गई है, लेकिन देखा गया है कि बाइक टैक्सी सेवा अभी भी लोकप्रिय ऐप रैपिडो पर चल रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एक ही तरह की सेवा के लिए अलग-अलग कंपनियों पर अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे हैं।

'शायरी नहीं शाह के लिए मुजरा भी करेंगे शिंदे'

यह महाराष्ट्र के लिए त्यौहार है। यह हमेशा से हमारी इच्छा रही है; हमें महाराष्ट्र के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। वे महाराष्ट्र को एक नई दिशा देंगे और ललकारेंगे। इतना ही नहीं संजय राउत ने बीते दिन एकनाथ शिंदे के एक बयान पर भी कड़ी आलोचना की और तंज कसा है। एकनाथ शिंदे के जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात वाले नारे पर राज्य में बवाल मच गया है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद के बाद यह मुद्दा महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में जय गुजरात का नारा लगाया। जिसके बाद राज्य में सियासी बवाल मच गया। विपक्षी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने डिप्टी सीएम पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करते हुए कहा, एकनाथ शिंदे अमित शाह के लिए मुजरा और मुशायरा भी कर सकते है। उनका मुजरा तो चल ही रहा है। मैं उनको पहचानता हूं, वो एक मराठी कविता भी नहीं पढ़ सकते। अगर उन्हें अमित शाह के आशीर्वाद से सत्ता में रहना है तो ये मुजरा उन्हें करना पड़ेगा, इसलिए किया है और करने दो। दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात का नारा लगाया था। इस दौरान अमित शाह ने गुजराती भाषा में लोगों को संबोधित किया था।

पुणे दुष्कर्म मामले में चौकाने वाले खुलासे

हालांकि, 200 क्राइम ब्रांच और 300 स्थानीय पुलिस अधिकारियों की जांच के बाद यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला और हिरासत में लिया गया युवक दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। वे पिछले एक साल से संपर्क में थे। युवक अक्सर बाणेर से महिला के घर पिज्जा और बर्गर जैसी खाने की चीजें भेजता था। घटना वाले दिन सुबह 5:30 बजे दोनों के बीच वॉट्सऐप पर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह सुबह करीब 7 बजे उसके फ्लैट पर आया और 8:30 बजे चला गया। इसी बीच उनका एक और परिचित फ्लैट पर आया था। उसने कुछ सेल्फी लीं और चला गया।

खबर संक्षेप

चावल मिल के गोदाम में लगी भीषण आग

खेड़ा। गुजरात के खेड़ा में शुक्रवार को एक चावल मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके से आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची।

दमकलकर्मी मौके पर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। फायर ऑफिसर चिराग गढ़वी ने कहा कि यह आग चावल मिल के पास प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है।

स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई 3 दोस्तों की मौत

सोनीपत। यहां के जीटी रोड सेक्टर 7 फ्लाईओवर पर वीरवार की रात स्कार्पियो व ट्रक की टक्कर हो गई स्कार्पियो में चेचेरे भाईयों समेत 4लोग सवार थे। जिनमें 3 की मौत हो गई। एक हालत गंभीर बनी हुई है।

स्कार्पियो अधिक रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित हो गई थी और डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी साइड टली गई। वहां से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी।

कोलकाता कांड में पुलिस ने रीक्रिएट किया सीन

कोलकाता। पुलिस के अधिकारी शुक्रवार को छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 4लोगों को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज ले गए। वहां पुलिस ने अपराध स्थल पर क्राइम सीन को रीक्रिएट किया।

तीन मुख्य आरोपियों पूर्व छात्र और संविदा कर्मचारी मनोजीत मिश्रा, वर्तमान छात्र प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद कोकॉलेज ले जाया गया।

नीट यूजी के नतीजों को चुनौती, अर्जी खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न में कथित त्रुटि के कारण नीट-यूजी 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, अब तक 69 की मौत

सुक्खू ने कहा-हर बेघर को हर माह मिलेंगे 5 हजार रुपए, शाह ने 4 सीएम से बात की

उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री

मुंबई हलचल / शिमला

हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही जारी है। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। आपदा पर सीएम सुक्खू कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध की तरह आपदा का सामना कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है।तबाही के बीच सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को कई राहत और बचाव योजनाओं की घोषणा की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और अन्य मंत्रियों के साथ सीएम सुक्खू ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से विस्थापित परिवारों को हर महीने 5 हजार रुपए मिलेंगे। जो परिवार राहत आश्रयों में रह रहे हैं और किराए का आवास ढूंढ रहे हैं, उन्हें 5 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सुक्खू ने कहा, प्रभावित परिवारों को भोजन और राशन की आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे। उधर, गृहमंत्री अमित शाह ने कई सीएम से बात की है।

प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ

सीएम ने कहा कि शिमला के एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज में फंसे 92 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं।

युद्धस्तर पर चल रहा सड़क, बिजली बहाली का काम

सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और जलापूर्ति बहाली का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। मुख्य सचिव समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। सरकार आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

14 जगहों पर बादल फटे

सुक्खू ने बताया कि इस साल मानसून की शुरुआत में ही हिमाचल में भारी तबाही देखने को मिली है। राज्य में 14 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा, हम अध्ययन कर रहे कि बादल फटने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस संबंध में बात की, जिन्होंने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सुक्खू ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें पूरी मदद देगी। नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम भी मिाचल पहुंच रही है।

कंगना और जयराम में अनबन

बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने का प्रयास किया तो जयराम ने रुकने को कहा

हिमाचल के मंडी जिले के अलग-अलग भागों में सोमवार रात बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़, भूस्खलन से मची तबाही के बाद प्रभावित क्षेत्रों की सुध नहीं लेने के आरोपों पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहीं सांसद कंगना रणौत ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जारी एक पोस्ट में लिखा- हिमाचल में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहलाने वाला है। मैंने मंडी के सराज और अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की

गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात

बचाव दल तैनात, केंद्र देगा हर संभव मदद

देश के कई राज्यों में मानसून के दस्तक देते ही भारी बारिश ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आई आपदा ने जमकर तबाही मचाई है। शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शाह ने एक्स पर लिखा, देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। जरूरतमंद लोगों के लिए इन राज्यों में एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर और टीमें भेजी जा सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।

धामी बोले- सुरक्षा का आश्वासन दिया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाह के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, शाह ने दूरभाष के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम सहित राज्य के विभिन्न आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।

इस संवेदनशीलता और सक्रियता के लिए शाह का आभार
उन्होंने कहा कि साथ ही राज्य के अन्य संवेदनशील जिलों में भी निगरानी रखते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। शाह का इस संवेदनशील, सक्रिय और सहृदय नेतृत्व के लिए हार्दिक आभार।

संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कोई नहीं हटा सकता: खरगे

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा-आरएसएस का भी कोई भी नेता संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद नहीं हटा सकता। कांग्रेस किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा की पाखंडी सोच को उजागर करते हुए कहा कि आरएसएस नेता ने देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद निकाल देने की बात कही है। लेकिन भाजपा के अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के सिद्धांतों के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की बात कही गई है। यदि भाजपा को धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद से इतनी नफरत है तो इन्हें अपने संविधान में क्यों लिखा?

मोदी सरकार की विफल रही विदेश नीति

खरगे ने भाजपा-आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि इन लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी और न ही वे अब देश के लिए कुछ सार्थक कर रहे हैं। हमेशा से माफी मांगना ही इनका काम रहा है। मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और पहलगाम आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात कही तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष देशहित में सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि वे पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेंगे, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति की वजह से सभी देश भारत के दुश्मन बन गए हैं। हालात ये हैं कि नेपाल भी भारत से दूर हो रहा है।

ट्रंप के दावे पर पीएम चुप क्यों?

खरगे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार की धमकी देकर भारत-पाक के बीच संघर्ष विराम कराने के दावों पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहादुरी का उदाहरण देते हुए कहा कि वे अमेरिका से नहीं डरीं और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी।

कांग्रेस का तेलंगाना से विशेष रिश्ता

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने आज तक हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा नहीं किया, जबकि राहुल गांधी वहां गए और लोगों का दुख-दर्द सुना। खरगे ने जातिगत जनगणना कराने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इसी मॉडल को अपनाना चाहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस का तेलंगाना के लोगों के साथ एक विशेष रिश्ता है। वह सोनिया गांधी ही थीं, जिन्होंने उनकी लंबे समय से लंबित मांग और अपना खुद का राज्य बनाने की इच्छा को पूरा किया था।

तेलंगाना में कई उपलब्धियां

खरगे ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली, किसानों के लिए 8,265 करोड़ रुपए की विशेष सहायता सहित अन्य कई उपलब्धियां गिनाईं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार और देश भर की अन्य कांग्रेस सरकारें रोहित वेमुला के नाम पर हर जगह एक कानून बनाएंगी, जो छात्रों को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के ... ख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, प्रदेश कां... गौड़ सहित कई व...

जीएसटीकी बैठक में छग की वाह वाह

वित्तमंत्री चौधरी ने बताया, कैसे पछाड़ा गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 18 फीसदी की रिकॉर्ड वृद्धि दर हासिल कर पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाती है, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू किए गए सुशासन और जीएसटी सुधारों की प्रभावशीलता को भी रेखांकित करती है। इस उपलब्धि के चलते छत्तीसगढ़ के वित्त एवं वाणिज्यिक-कर मंत्री ओपी चौधरी को केंद्र सरकार ने जीएसटी राजस्व वृद्धि और सुधारों के लिए गठित मंत्रियों के चार महत्वपूर्ण विशेष समूहों में शामिल किया है।

दिल्ली में विशेष समूह की बैठक में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी

शुक्रवार को दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रियों के विशेष समूह की बैठक में चौधरी ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में जीएसटी राजस्व के विश्लेषण, आर्थिक कारकों के प्रभाव, कर लीकेज रोकने के उपायों, और राजस्व वृद्धि के लिए नीतिगत सुझावों पर गहन चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य जीएसटी परिषद को ठोस सुझाव प्रदान करना था, ताकि देशभर में जीएसटी प्रणाली को सशक्त किया जा सके। चौधरी ने बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। बीफा, जीएसटी प्राइम, और ई-वे बिल पोर्टल जैसे टूल्स के माध्यम से बोगस व्यवसायियों को पंजीकरण के दौरान ही चिह्नित करने और फर्जी बिलों पर नियंत्रण करने की रणनीति की प्रस्तुति दी तो सभी की खूब सराहना मिली। उन्होंने बताया कि इन उपायों से न केवल कर टैक्स लीकेज पर अंकुश लगाया जा सका, बल्कि राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई।

व्यापारियों के लिए राहत, राजस्व में वृद्धि

चौधरी ने बताया कि छग सरकार ने जीएसटी प्रणाली को पारदर्शी, व्यापारी-अनुकूल, और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले बजट में ई-वे बिल की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया, जिससे लगभग 75 फीसदी ई-वे बिल जनरेशन की आवश्यकता समाप्त हो गई।

18 फीसदी की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन वृद्धि

उच्च स्तरीय बैठक में ओपी चौधरी ने राज्य की उपलब्धियों को अन्य प्रदेशों के लिए एक 'माइल स्टोन' के रूप में रखते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने जीएसटी और वैट से कुल 23 हजार 448 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38 फीसदी है। 18 फीसदी की जीएसटी वृद्धि दर के साथ छत्तीसगढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का विषय है और यह दर्शाती है कि छोटे राज्य भी सही नीतियों और सुधारों के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। राज्य के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रह और संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हुई है।

चौतरफा प्रशंसा मिली वित्त मंत्री चौधरी की रणनीति को: वित्त मंत्री ओपी चौधरी बैठक में सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खूब प्रशंसा मिली। उनके नेतृत्व में विभाग ने डेटा आधारित विश्लेषण, तकनीकी निगरानी, और व्यापारी जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। उनकी इन उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें जीएसटी सुधारों के लिए गठित विशेष मंत्रियों के समूह में शामिल किया है।

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट में बोले सिंघवी

यह अनोखा मामला, न कोई संपत्ति है, न उसका उपयोग या प्रदर्शन

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि ईडी का यह मामला 'वास्तव में बेहद अजीब और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, 'यह मामला सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि बहुत ही अनोखा है। यह कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लेकिन इसमें न कोई संपत्ति है। न संपत्ति का उपयोग या प्रदर्शन शामिल है।' मामले की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, 'हर कंपनी को कानून के तहत अपनी देनदारी हटाने की अनुमति होती है। हमने भी वही किया। हमने एजीएल का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर किया ताकि एजीएल कर्जमुक्त हो जाए।' उन्होंने बताया कि यंग इंडियन एक गैर-लाभकारी कंपनी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी लाभ, बोनस, वेतन या लाभांश नहीं बांट सकती।

'ईडी ने वर्षों तक कुछ नहीं किया' : अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने वर्षों तक इस मामले में कुछ नहीं किया और अचानक एक निजी शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा, 'ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अगर नेशनल हेराल्ड किसी गैर-कांग्रेसी संस्था के पास चला जाए तो यह ऐसा होगा जैसे 'हैमलेट नाटक' हो लेकिन उसमें डेनमार्क का राजकुमार न हो।'

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के आरोप लगाए हैं। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजीएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हड़प लिया। यह वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी। आरोप है कि यंग इंडियन ने सिर्फ 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजीएल की पूरी संपत्ति अपने हाथ में ले ली।

रिपोर्ट

वैज्ञानिकों ने खोजे 3 नए प्रोटीन

कैंसर और तेजी से बढ़ती उम्र के खिलाफ बड़ी कामयाबी!

मुंबई हलचल / सिडनी

कैंसर आज दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2020 में ही कैंसर ने लगभग 10 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इस पर एक शोध किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे प्रोटीन के समूह के पहचान की है जो कैंसर और उम्र से संबंधित बीमारियों के इलाज करने के तरीकों को बदल सकता है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, सिडनी में स्थित चिल्ड्रेंस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधतर्ताओं ने ये खोज की है।

क्या है यह खोज?

शोध करने वाली वैज्ञानिकों की टीम को पता चला है कि कुछ प्रोटीन टेलोमेरेज नाम के एक बहुत ही खास एंजाइम को कंट्रोल करते हैं। यह एंजाइम सेल्स के बंटवारे के समय डीएनए को खराब होने से बचाता है। टीम ने बताया कि इस खोज से यह साफ होता है कि टेलोमेरेज कैसे हमारे स्वस्थ रहने और उम्र को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से रोकता है।

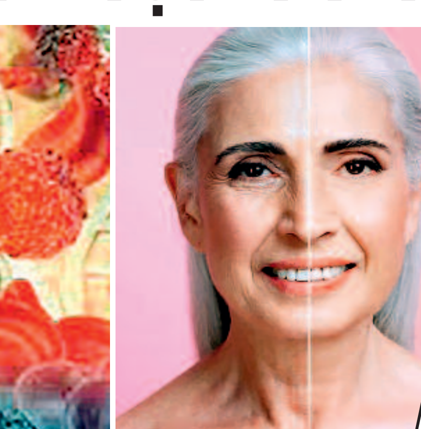

टेलोमेरेज और प्रोटीन की नई-नई खोज

आपको बता दें कि टेलोमेरेज एक एंजाइम है जो हमारे क्रोमोसोम को ठीक रखने में मदद करता है। इन सिरों के टेलोमेयर कहते हैं जो हमारे डीएनए को नुकसान से बचाते हैं। हालांकि, टेलोमेरेज स्टेम सेल्स और हमारे इम्यून सेल्स के लिए जरूरी है। लेकिन, कैंसर सेल्स अक्सर इन्हीं टेलोमेरेज का गलत फायदा भी उठाती हैं। इसका इस्तेमाल केंसर सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ने कते लिए करती हैं, जिससे कैंसर और फैलता है। सीएमआरआई के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन की नया ग्रुप खोजा है, जो इस एंजाइम को कंट्रोल कर सकते हैं।

कैंसर के इलाज में नई उम्मीद

नेचर कम्यूनिकेशन पत्रिका में छपी एक नई खोज कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगाती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि नोनो, एसएफपीक्यू और पीएसपीसी1 नाम के 3 खास प्रोटीन टेलोमेरेज को क्रोमोसोम के बिल्कुल आखिर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर कैंसर सेल्स में इन प्रोटीन्स को काम करने से रोक दिया जाए तो टेलोमेरेज धीमा पड़ जाता है और कैंसर सेल्स की बढ़ोतरी को रोकता है।

बुढ़ापे की बीमारियों का इलाज

इस अध्ययन के मुख्य लेखक अलेक्जेंडर सोबिनॉफ ने कहा, हमारी जांच से जो नतीजे निकले वो बताते हैं कि यह प्रोटीन एक तरह से आणविक यातायात नियंत्रक की तरह काम करते हैं। सोबिनॉफ ने आगे बताया की इन प्रोटीनों के बिना टेलोमेरेज ठीक से काम नहीं कर सकता और टेलोमेयर को ठीक से नहीं बना पाता। सीएमआरआई में टेलोमेर लंबाई विनियमन इकाई की प्रमुख और इस रिसर्च की सीनियर लेखक हिल्डा पिकेट का कहना है कि, टेलोमेरेज काम कैसे करता है। इसे समझने से कैंसर और बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों से जुड़ी समस्याओं के लिए नए इलाज खोजने के रास्ते खुले हैं।

बातचीत के बाद भारतीय दल वापस भारत लौट आया

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 9 जुलाई से पहले होने की बढ़ी उम्मीद

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत करने के बाद भारतीय दल वाशिंगटन से लौट आया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौते को नौ जुलाई से पहले अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, लेकिन कृषि और वाहन सेक्टर में कुछ मुद्दों को अभी भी सुलझाए जाने की जरूरत है, इसलिए चर्चा जारी रहेगी। भारतीय दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। वे वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव हैं।

अधिकारी ने कहा कि वार्ता अंतिम चरण में है और इसके निष्कर्ष की घोषणा नौ जुलाई से पहले होने की उम्मीद है, जो भारत सहित कई देशों पर लगाए गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क के 90-दिवसीय निलंबन की अवधि का अंतिम दिन है। अधिकारी ने कहा, "भारतीय टीम वाशिंगटन से वापस आ गई है। वार्ता जारी रहेगी। कृषि और वाहन क्षेत्रों में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है।

भारत ने कृषि व डेयरी पर अपना रुख कड़ा रखा

पिछले साल अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर 89 अरब डॉलर के वाहन कलपुर्जों का आयात किया। इसमें मेक्सिको का हिस्सा 36 अरब डॉलर, चीन का 10.1 अरब डॉलर और भारत का हिस्सा सिर्फ 2.2 अरब डॉलर का था। कृषि क्षेत्र में, अमेरिका डेयरी उत्पादों, सेब, वृक्षों से प्राप्त मेवों और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे उत्पादों पर शुल्क रियायतें चाहता है। हालांकि, राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण, भारत के लिए कृषि क्षेत्र में कोई रियायत देना कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। भारत ने अब तक जितने भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, उनमें से किसी भी व्यापारिक साझेदार के लिए डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत देने पर अपना रुख कड़ा कर लिया है।

- समझौते को 9 जुलाई से पहले अंतिम रूप देने की संभावना
- कृषि और वाहन सेक्टर में कुछ मद्दे अभी सुलझना बाकी
- भारतीय दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल कर रहे

भारत श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क रियायतें चाहता है : *अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, वाहन, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर शुल्क रियायतें चाहता है। दूसरी ओर, भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते में कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क रियायतें चाहता है।*

भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 फीसदी शुल्क लगाया था

भारतीय टीम 26 जून से दो जुलाई तक अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए वाशिंगटन में थी।ट्रंप के जवाबी शुल्क का निलंबन नौ जुलाई को समाप्त हो रहा है। दो अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत मूल शुल्क अभी भी लागू है। भारत अतिरिक्त 26 प्रतिशत शुल्क से पूरी छूट चाहता है।

वाहन क्षेत्र में 25 फीसदी शुल्क को लेकर मुद्दा उठाया

भारत ने वाहन क्षेत्र में 25 प्रतिशत शुल्क को लेकर मुद्दा उठाया है। इसने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की सुरक्षा समिति में इस मामले को उठाया है। भारत ने डब्ल्यूटीओ को यह भी बताया है कि उसने इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को भेजे एक पत्र में कहा है कि 26 मार्च, 2025 को अमेरिका ने भारत में बने या वहां से आयातित यात्री वाहनों और हल्के ट्रकों तथा कुछ वाहन कलपुर्जों के आयात पर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क वृद्धि के रूप में एक उपाय अपनाया है। वाहन कलपुर्जों पर यह उपाय तीन मई, 2025 से असीमित अवधि के लिए लागू होगा।

पंचायत चुनाव से पहले ओपी राजभर की दबाव की राजनीति, योगी से मिले, मोदी से भी मिलेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी सुभासपा अध्यक्ष औ योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव से पहले दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। शुक्रवार को वह मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी से मिले और कोटे में कोटा का पुराना राग छेड़ दिया है। उन्होंने पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में बंटवारे की मांग सीएम योगी से कर दी। यही नहीं, अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी यह प्रस्ताव रखने दिल्ली जाएंगे। सीएम योगी से मुलाकात के समय ओपी राजभर के बेटे और सुभासपा के महासचिव अरुण राजभर भी मौजूद रहे। राजभर ऐसे समय योगी से मिले और कोटे में कोटे की मांग रखी, जब तीन दिन पहले ही उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी तस्वीर के साथ अलग तरह से जन्मदिन की बधाई दी थी। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजभर पिछले दो विधानसभा चुनाव के दौरान तीन बार पाला बदल चुके हैं। 2017 में राजभर भाजपा के साथ थे। योगी की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। इसके बाद भी ऐसी स्थिति बना दी कि योगी ने

उनको बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा लेकिन खास सफलता नहीं मिलने पर दोबारा बीजेपी के करीब आएं और एक बार फिर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने में सफल हो गए।

पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों के मिले अलग आरक्षण : ओपी राजभर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति आरक्षण में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग से कोटा दिए जाने की मांग की है। राजभर का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति में अति व सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित किया जाना समय की मांग है। मौजूदा व्यवस्था में इन जातियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण का लाभ ओबीसी और एससी की कुछ चुनिंदा जातियों के लोग उठा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पुलिस भर्ती परीक्षा भी है। 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 19000 से ज़्यादा ओबीसी की मजबूत जातियों ने ही उठाया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के उद्देश्य से सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की है। इसमें पिछड़ी जाति को कोटे को तीन भागों पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और सर्वाधिक पिछड़ी जाति में बांटने की सिफारिश की गई है।

REST IN PEACE

शिवा देवनाथ

तुम इतनी जल्दी चले जाओगे ऐसा कभी सोचा नही था। आज शब्द गूंगे हैं, और दिल भारी है। मैंने न सिर्फ एक शानदार पत्रकार, बल्कि एक नेकदिल इंसान, एक हंसमुख छोटा भाई जैसा दोस्त, **शिवा देवनाथ** को खो दिया। शिवा ने **पत्रकारिता में फर्श से अर्श तक का सफर खुद के दम पर तय किया**। खबरों के पीछे की असली कहानी को ढूंढने की कला उसकी प्रतिभा को दर्शाता है। उसने हर खबर को ज़िम्मेदारी और जज्बे से लिखा। मिड डे जैसे प्रतिष्ठित अखबार में उसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मिड डे छोड़ने के बाद भी वह हमेशा मुस्कुराता रहा, हर परिस्थिति में सकारात्मक बना रहा, यही उसकी पहचान बनी थी। पर अचानक इतनी कम उम्र में उसका जाना हम सभी को तोड़ गया है, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगी। **परमात्मा उसके परिवार को संबल और शक्ति दे,** जिन्हें अब आगे की जिंदगी शिवा के बिना जीनी है। हमारी तरफ से अंतिम सलाम, शिवा। तुम भले हम सबको छोड़ कर ईश्वर को प्राप्त हुए हो, पर तुम्हारी यादें हमेशा बनी रहेगी। ॐ शांति

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

आमिर की सितारे जमीन पर का खेल खल्लास

आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुई है। फिल्म ने 14 दिन में 135 करोड़ का कारोबार कर लिया है। फिल्म 90 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। उस लिहाज से फिल्म ने ठीक-ठाक कारोबार कर लिया है। आने वाले वक्त में इसका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके हिसाब से फिल्म हिट हुई या नहीं यह तय किया जाएगा। लेकिन अभी फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की कमाई बाकी है। ऐसे में फिल्म बजट के अलावा अच्छा मुनाफा वसूल करने में कामयाब हुई है। यह कहा जा सकता है। आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया और आने वाले वक्त में कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 10 करोड़ की ओपनिंग हासिल की थी। दूसरे दिन शनिवार को 20.2 करोड़ तीसरे दिन रविवार को 27.25 करोड़, पहले सोमवार को 8.5 करोड़, मंगलवार को 8.5 करोड़, बुधवार को 7.5 करोड़, सातवें दिन गुरुवार को 6.5 करोड़, इस तरह फिल्म ने पहले हफ्ते में 88.9 करोड़ का कारोबार किया। दूसरे हफ्ते में यह फिल्म 46.69 करोड़ कमाने में कामयाब हुई। कुल मिलाकर फिल्म 135 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया था। 14वें दिन फिल्म में 2.69 करोड़ का कारोबार किया था। 15वें दिन फिल्म से 2 करोड़ के आसपास कारोबार की उम्मीद है।

रान्या राव की बढ़ी मुश्किलें

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रान्या राव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ईडी ने रान्या की करीब 34.12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने ये कार्रवाई कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर जिलों में की है। जब्त की गई संपत्तियों में रान्या राव और उनके साथियों के नाम पर रिहायशी घर, प्लॉट, इंडस्ट्रियल लैंड और एग्रीकल्चर लैंड शामिल हैं। ईडी ने यह संपत्तियां (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत अटैच की हैं, यह कहते हुए कि ये संपत्तियां उस अवैध कमाई के बराबर हैं जो अपराध से अर्जित की गई थी, लेकिन अभी तक ट्रेस नहीं की जा सकी है। जांच की शुरुआत 7 मार्च 2025 को CBI द्वारा दर्ज की गई एक FIR से हुई थी। ये FIR डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की शिकायत पर आधारित थी। इसमें दो विदेशी नागरिक एक ओमानी और एक UAE निवासी को मुंबई एयरपोर्ट पर 21.28 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 18.92 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इससे कुछ दिन पहले, 3 मार्च को, रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वह 14.2 किलो अवैध गोल्ड (24 कैरेट फॉरेन ओरिजिन) के साथ पकड़ी गई थीं, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ थी। उनके घर पर छापेमारी में भी 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ की गोल्ड जूलरी बरामद हुई थी।

ABVM AGRAWAL JATIYA KOSH'S GHANSHYAMDAS JALAN COLLEGE
Estd. - 2014

G.D. JALAN COLLEGE

Affiliated to University of Mumbai & M.S. Board

(MARWARI MINORITY) NAAC Accredited with B+ Grade, ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COLLEGE

College Code : 527

Junior College

F.Y.J.C/ S.Y.J.C (Science & Commerce)

Degree College

B. Com • B.A.F • B.Sc.I.T • B.M.S • B.Sc

ADMISSIONS OPEN

Contact Number : 9326346900 / 9326335467

Upper Govind Nagar, Malad (East)